एशिया की टॉप कंपनियों में भारत को जगह नहीं

- टॉप 100 में भारत की 34 कंपनियां
- कर्मचारियों के भरोसे से तय हुई रैंकिंग

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली , 14 सितंबर एशिया की सबसे अच्छी कंपनियों में काम करने की बात हो तो भारत की मौजूदगी इस बार काफी मजबूत रही है. ग्रेट प्लेस टू वर्क की 'बेस्ट वर्कप्लेस इन एशिया 2026' की बड़ी कंपनियों की टॉप-100 लिस्ट में भारत में काम करने वाली 34 कंपनियां शामिल हैं. हालांकि एशिया की टॉप-10 कंपनियों में भारत की कोई कंपनी जगह नहीं बना पाई है. टॉप-10 में हिल्टन सबसे ऊपर है.

इसके बाद मैरियट इंटरनेशनल, सिस्को, एब्वी, डीएचएल, इंटरकांटिनेंटल होटल्स ग्रुप, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, टेलीपरफॉर्मेंस, एक्सेंचर और कैपेला का नाम है. बड़ी कंपनियों की कैटेगरी में भारत से शामिल कंपनियों में फ्लिपकार्ट ग्रुप, इन्फोसिस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, रिलायंस रिटेल, बजाज फाइनेंस, मैक्स हेल्थकेयर, आय फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जेंसर टेक्नोलॉजी, एक्सपेरियन, एडेलवेइस लाइफ और हैवलेट-पैकार्ड जैसे नाम हैं. यानी टॉप 100 में शामिल कंपनियों में करीब एक तिहाई ऐसी हैं जो भारत में काम करती हैं. 'ग्रेट प्लेस टू वर्क इन इंडिया' के सीईओ बलबीर सिंह के मुताबिक इन कंपनियों में बड़ी संख्या बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस और आईटी सेक्टर की है.इस लिस्ट की खास बात यह है कि रैंकिंग सिर्फ कंपनी के आकार, रेवेन्यू या ब्रांड की लोकप्रियता देखकर नहीं बनाई गई. इसमें सबसे अहम भूमिका कर्मचारियों के फीडबैक की रही. इस स्टडी में एशिया और पश्चिम एशिया के करीब 89 लाख कर्मचारियों के अनुभवों को शामिल किया गया. इनमें 38 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के जवाबों इस्तेमाल रैंकिंग तैयार करने में हुआ.

एशिया की टॉप 10 बड़ी कंपनियां

क्र.	कंपनी
1.	हिलटन
2.	मैरियोट इंटरनेशनल
3.	सिस्को
4.	एबी
5.	डीएफएल
6.	इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप
7.	माइक्रोन टेक्नोलॉजी
8.	टीसीएल
9.	एसेंचर
10.	कैपेला

छोटी ने बेहतर स्कोर के साथ बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ा

कर्मचारी अनुभव के मामले में छोटी और मिडियम कंपनियां बड़ी कंपनियों से आगे रहीं. छोटी और मिडियम कंपनियों का कुल वर्कप्लेस एक्सपीरियंस स्कोर 96% रहा, जबकि बड़ी कंपनियों का स्कोर 91% था. ट्रस्ट इंडेक्स में भी छोटी और मिडियम कंपनियां 93%, स्कोर के साथ आगे रहीं, जबकि बढ़ी कंपनियों का स्कोर 89% रहा. भारत की मौजूदगी सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है. छोटी और मिडियम कैटेगरी में भी 6 भारतीय संगठनों को जगह मिली है. इनमें एनआईए इस्टीट्यूशंस वाडम इंडिया, शैलेट होटल्स, सेरेटिका रिन्यूवल्स इंडिया, किंबल और लॉर्ड महाशिय सर्विसेज शामिल है. 'वेस्ट वर्कप्लेस टू वर्क' में कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट को भी अहम माना गया है. इस क्षेत्र में पॉजिटिव विकिंग का स्कोर 88% से बढ़कर 90% हो गया. मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सोशल सर्विस और गवर्नमेंट एजेंसियों ने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के मामले में 93% का स्कोर हासिल किया.

एआई के खतरे से शेयरों में भूचाल

- एआई सुरक्षा को लेकर बढ़ी निवेशकों की चिंता
- एसके हाइनिक्स 5.3%, सैमसंग 3.7% नीचे

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 14 सितंबर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते विकास को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं अब शेयर बाजार पर भी असर डालने लगी हैं. सोमवार को एआई और सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली.

प्रमुख अमेरिकी एआई कंपनियों के प्रमुखों की ओर से एआई विकास की रफ्तार धीमी करने की अपील के बाद निवेशकों में चिंता बढ़ी है. एशियाई कारोबार के दौरान नैस्डैक ई-मिनी वायदा 1.3 फीसदी तक गिर गया, जबकि जापान में ओपनएआई के निवेशक सॉफ्टबैंक के शेयर एक समय 13.2 फीसदी तक टूट गए.

एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोडेई ने एआई के गलत इस्तेमाल से जुड़े बढ़ते खतरों का हवाला देते हुए विकास की गति धीमी करने की अपील की. उन्होंने चेतावनी दी कि अगले छह से 12 महीनों में एआई एजेंट इतने सक्षम हो सकते हैं कि वे इंटरनेट के बड़े हिस्से पर नियंत्रण हासिल करने की स्थिति में पहुंच जाएं. ओपनएआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क ने भी उनकी चिंताओं से सहमति जताई है.

रेपो रेट बढ़ेगा, महंगे होंगे कर्ज

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली , 14 सितंबर लोन लेने वालों के लिए आने वाले महीने मुश्किल हो सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक अक्टूबर में रेपो रेट बढ़ाने की तैयारी कर सकता है. एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अक्टूबर की बैठक में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी की जानी चाहिए.

- अक्टूबर और दिसंबर में 0.25% बढ़ोतरी संभव
- होम और कार लोन की ईएमआई बढ़ेगी

इसके बाद दिसंबर में भी इतनी ही बढ़ोतरी की जरूरत पड़ सकती है. अगर ऐसा होता है तो होम लोन, कार लोन और दूसरे फ्लोटिंग रेट वाले कर्ज की ब्याज दर और ईएमआई बढ़ सकती है. जमाकर्ताओं के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है.

रेपो रेट बढ़ने पर बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थाएं एफडी की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी कर सकती हैं यानी जिन लोगों के पास एफडी है या जो आने वाले महीनों में एफडी कराने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पहले के मुकाबले बेहतर ब्याज मिल सकता है.

भू-राजनीतिक तनाव से बढ़ रहा महंगाई का दबाव

एसबीआई रिसर्च के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमत में तेज बढ़ोतरी और दुनिया में बने भू-राजनीतिक तनाव से महंगाई का दबाव बढ़ रहा है. कच्चे तेल की कीमत हाल में 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है. रिपोर्ट के एक अनुमान के मुताबिक अगले 15 दिनों में कीमत 123 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है. हालांकि यह खराब स्थिति का अनुमान है, सामान्य स्थिति का नहीं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महंगाई का दबाव अब कुछ चुनिंदा चीजों तक सीमित नहीं है.

स्टील कचरे से बनी सबसे लंबी सड़क

- जिंदल स्टील का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
- 1.85 किलोमीटर लंबी चार लेन सड़क तैयार

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली , 14 सितंबर जिंदल स्टील लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 'स्टील स्लैग' से बनी दुनिया की सबसे लंबी सड़क तैयार कर गिनीज वर्ल्ड सड़क रिकॉर्ड से मान्यता हासिल की है.

कंपनी ने यह उपलब्धि सीएसआईआर-केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीआरआरआई) के सहयोग से हासिल की है. करीब 1.85 किलोमीटर लंबी और चारलेन वाली इस सड़क के निर्माण में लगभग 2 लाख टन प्रसंस्कृत स्टील स्लैग का इस्तेमाल किया गया है. इस प्रौद्योगिकी में सड़क निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक पत्थर और अन्य चीजों की जगह स्टील स्लैग का उपयोग किया गया है.

जिंदल स्टील के चेयरमैन नवीन जिंदल ने कहा कि यह उपलब्धि दिखाती है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग मिलकर औद्योगिक उप-उत्पादों को राष्ट्र निर्माण के लिए उपयोगी संसाधनों में बदल सकते हैं. उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा ऐसी नई प्रौद्योगिकी पर आधारित होनी चाहिए जो आर्थिक मूल्य पैदा करने के साथ पर्यावरण की भी रक्षा करें. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस परियोजना को वैज्ञानिक नवोन्मेषण को वास्तविक बुनियादी ढांचे में बदलने का मजबूत उदाहरण बताया.

पश्चिमी देशों से लौट रहे भारतीय प्रतिभाशाली

- वीजा नियम सख्त, बढ़ी जीवनयापन की लागत
- अमेरिका, ब्रिटेन-कनाडा से वापसी तेज

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली , 14 सितंबर. पश्चिमी देशों में वर्क वीजा, पोस्ट-स्टडी परमिट और नागरिकता के नियमों में जारी अभूतपूर्व कड़ाई ने वैश्विक प्रतिभा प्रवाह का रुख मोड़ दिया है जिससे अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा से कुशल भारतीय पेशेवरों और छात्रों की बड़े पैमाने पर स्वदेश वापसी शुरू हो गई है.

रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में एच-1बी वीजा पर अनिश्चितता, ब्रिटेन में ग्रेजुएट रूट वीजा पर पाबंदियां, और कनाडा द्वारा स्टडी परमिट व परमानेंट रेजिडेंसी कोटा में की गई भारी कटौती के कारण पश्चिमी सपनों पर पानी फिरता दिख रहा है. बीते दशकों में जहां 'ब्रेन ड्रेन' भारत की सबसे बड़ी चिंता थी, वहीं अब पश्चिमी देशों में बढ़ती छंटनी, जीवनयापन की लागत और इमिग्रेशन विरोधी पॉलिसीज के चलते यह ट्रेंड 'रिवर्स ब्रेन ड्रेन' में बदल चुका है. हजारों टेक प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स और मैनेजमेंट स्नातक अब स्वदेश लौटकर भारत की तेज आर्थिक वृद्धि का हिस्सा बन रहे हैं. यह रणनीतिक बदलाव भारतीय इकोनॉमी और कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बड़ा अवसर बनकर उभरा है.

जॉब मार्केट में भी दिख रहा बदलाव

रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा ऑटोमोटिव और एक्सिस बैंक जैसी कंपनियों ने भी भारत लौटने वाले लोगों के लिए नौकरियां निकाली है. वीजा खत्म होने के बाद पटेल इस साल की शुरुआत में भारत आ गई. वह अकेली नहीं है. 25 साल के अरुंदव एस भारत में ऐसी नौकरियां ढूंढ रहे है जिनसे उन्हें सालाना कम से कम 9 लाख रुपए मिल सकें. उन्होंने कहा कि यूके में मैं जो भी कमाता हूं, वह मेरे खर्चों में ही चला जाता है जो पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ गए हैं लेकिन अरुंदव तब तक लौटने को तैयार नहीं है जब तक उन्हें ऐसी नौकरी न मिल जाए जिससे वे अपना लोन चुका सकें, यह बदलाव जॉब मार्केट में भी दिख रहा है.

कच्चा तेल 107 डॉलर पार पेट्रोल-डीजल स्थिर

- ब्रेंट क्रूड 3% उछलकर 107.66 डॉलर प्रति बैरल

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 14 सितंबर. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल आया है, लेकिन इसका असर फिलहाल भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ा है.

तेल कंपनियों ने सोमवार सुबह छह बजे पेट्रोल-डीजल के नए भाव जारी किए, जिनमें प्रमुख शहरों में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 3 फीसदी बढ़कर 107.66 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है. वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमत भी 2.75 फीसदी बढ़कर 102.78 डॉलर प्रति बैरल हो गई है. भारत अपनी जरूरत का करीब 80 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का असर घरेलू ईंधन बाजार पर पड़ने की आशंका रहती है.

ब्रिक्स देशों में कारोबार बढ़ाने पर बनी एक राय

भारत-रूस व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर जोर

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 14 सितंबर. वैश्विक व्यापार में बढ़ती टैरिफ चुनौतियों के बीच ब्रिक्स देशों ने सामूहिक सहयोग और आर्थिक एकजुटता पर जोर दिया है.

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन उद्योग जगत और विशेषज्ञों ने कहा कि समूह अब केवल राजनीतिक या आर्थिक चर्चा का मंच नहीं, बल्कि वैश्विक दक्षिण की सामूहिक आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है. उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के मुताबिक, सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग बढ़ने से मौजूदा व्यापारिक दबावों का सामना करने में मदद मिलेगी. एसडब्ल्यूएफआई के चेयरमैन और आईब्रिक्स 2026 के लीड को-चेयर लक्ष्मी नारायणन ने कहा कि मौजूदा टैरिफ चुनौतियां ब्रिक्स देशों की वजह से नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापारिक परिस्थितियों और अमेरिकी नीतियों के प्रभाव से पैदा हुई हैं. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश इन चुनौतियों का सामूहिक रूप से सामना करने पर सहमत हुए हैं. उनके मुताबिक शिखर सम्मेलन से तीन प्रमुख परिणाम सामने आए हैं—द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, भारत-चीन सीमा मुद्दे के समाधान की दिशा में सकारात्मक सहमति और भारत-रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य.

समाचार विशेष

हल्द्वानी से मिशन-2027 का शंखनाद

हल्द्वानी, 14 सितंबर. उत्तराखंड भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति में बुधवार को भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आई. यहां रामपुर रोड स्थित एक होटल में प्रदेश भर से जुटे सैकड़ों पदाधिकारियों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरा. वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूती दिलाने का मंत्र दिया.

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा में राजनीति सत्ता नहीं साधना है, भोग नहीं त्याग है और तपस्या है. उत्तराखंड सरकार विकास को प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है और भाजपा राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रही है. उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वंदे मातरम् और तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है, जबकि पिछली सरकारों ने देश की जनसांख्यिकी बिगाड़ने का काम किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि बूथ और मंडल को मजबूत करना है, संघर्ष और परिश्रम के बल पर ही 2027 में हैट्रिक लगेगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचा है, हमने जो कहा वो किया, चारधाम, ऑलवेदर रोड, पर्यटन और रोजगार पर सरकार का फोकस है और सरकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाना है. प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि संगठन ही सरकार की ताकत है और 2027 में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना तय है.

भाजपा लगाएगी जीत की हैट्रिक

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार शानदार कार्य कर रही है. सरकार के सभी कार्य राज्य के संवर्धन और विकास के लिए हैं. उन्होंने कहा कि वह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जिस राज्य को अटल जी ने बनाया हमारी सरकारें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन्हें विकसित राज्य बना रही हैं. भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पहुंचे बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकारें बनने के बाद से ही राज्य विकास के नए आयाम छू रहा है. कांग्रेस के शासन में दिल्ली और देहरादून तक पहुंचने में 7 से 8 घंटे लगते थे अब केवल दो से तीन घंटे लगते हैं, इसकी कोई पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था.

मातोश्री पहुंचीं डीएमके सांसद कनिमोझी!

कांग्रेस से नाराजगी के कारण बदलेगा समीकरण?

मुंबई, 14 सितंबर. राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर दरार की अटकलें उस समय और तेज हो गईं, जब डीएमके की प्रमुख नेता और लोकसभा सांसद कनिमोझी करुणानिधि अचानक मुंबई स्थित मातोश्री पहुंचकर उद्धव ठाकरे से मिलीं.

एक राज्य (तमिलनाडु) में अपना मजबूत वर्चस्व रखने वाली डीएमके के वरिष्ठ नेता की महाराष्ट्र के दिग्गज क्षेत्रीय नेता से इस मुलाकात को देश के सियासी हलकों में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है.

तमिलनाडु के हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद

द्रमुक और कांग्रेस के बीच संबंधों में भारी कड़वाहट आ चुकी है. तमिलनाडु में कांग्रेस ने अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया, जिससे डीएमके और कांग्रेस का बीते 20 वर्षों पुराना गठबंधन टूट गया. इतना ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्षेत्रीय दल वीसीके के प्रमुख थिरुमावलवण को फोन कर टीवीके का समर्थन करने का अनुरोध भी किया था. कांग्रेस के इस कदम से नाराज होकर सांसद कनिमोझी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अपनी पार्टी के सांसदों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था करने का अनुरोध किया. अब तक द्रमुक के सांसद लोकसभा में राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों के बगल में ही बैठते थे. इस बीच, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन और द्रमुक का खुलकर समर्थन किया है, जिसके लिए कनिमोझी ने अखिलेश यादव का आभार जताया. ऐसे तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल के बीच कनिमोझी का मातोश्री पहुंचना बेहद अहम माना जा रहा है.

क्षेत्रीय शक्तियों की एकजुटता और भविष्य का रुख

परिसीमन विधेयक पर उद्धव ठाकरे का स्पष्ट रुख रहा है कि 33 फीसदी महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाना चाहिए, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्रचना जैसे राष्ट्रीय विषय पर जल्दबाजी की बजाय व्यापक राष्ट्रीय चर्चा और शोध होना आवश्यक है. मुलाकात के बाद शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद अनिल देसाई ने कहा कि यह एक बेहद सौहार्दपूर्ण बैठक थी. उन्होंने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु में डीएमके और महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) दोनों ही अपने-अपने राज्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियां हैं.

संजय झा की तिकड़ी की कवायद पर लगा ब्रेक

पटना, 14 सितंबर. बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भीतर राजनीतिक समीकरणों को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं. बिहार विधान परिषद के सभापति पद को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की ओर से कथित तौर पर दावेदारी की कोशिश की गई.

राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस पद को जदयू के खाते में लाने की रणनीति पर विचार किया था. हालांकि, इस कवायद के बीच फिलहाल मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के संकेत नहीं हैं और अवधेश नारायण सिंह के ही सभापति बने रहने की संभावना है. सूत्रों का दावा है कि जदयू के संगठनात्मक चुनाव के बाद पार्टी में संजय झा की सक्रियता बढ़ी. इसके बाद भाजपा पर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति के तहत कुछ महत्वपूर्ण पदों को लेकर चर्चा शुरू हुई. इसी क्रम में विधान परिषद के सभापति पद को भी जदयू के लिए हासिल करने की बात सामने आई. बताया जाता है कि संजय झा, विजय कुमार चौधरी और ललन सर्राफ के बीच इस पद को लेकर विचार-विमर्श हुआ था. कथित तौर पर ललन सर्राफ को सभापति बनाने की संभावना पर भी चर्चा हुई. हालांकि, जदयू की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. बिहार में भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन सरकारों के दौरान विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सभापति के पदों को लेकर एक राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की परंपरा रही है. दोनों दलों के बीच महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के बंटवारे को गठबंधन की व्यवस्था का हिस्सा माना जाता है. जब जदयू ने राजद के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब राजद के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष बने थे, जबकि जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर को विधान परिषद का सभापति बनाया गया था. जदयू के संगठनात्मक चुनाव के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर नई चर्चाएं शुरू हुईं. राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, इसी दौर में भाजपा के साथ गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी और प्रभाव को लेकर जदयू की ओर से दबाव बनाने की कोशिश हुई. सभापति पद को लेकर सामने आई चर्चा को भी इसी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.

नीतीश की पसंद निर्णायक

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, अवधेश नारायण सिंह को नीतीश कुमार की पसंद माना जाता है. विभिन्न दलों के बीच उनकी स्वीकार्यता भी उनके पक्ष में जाती है. ऐसे में उनके स्थान पर किसी दूसरे नेता को लाने के लिए गठबंधन के भीतर व्यापक सहमति जरूरी होगी.

विशेष | आईसा ने इस बार दूसरे कम्युनिस्ट छात्र संगठन एसएफआई से हाथ मिलाया है

डूसू चुनाव में 'जेन जी' की असली परीक्षा

नई दिल्ली, 14 सितंबर. दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी डूसू का चुनाव 18 सितंबर को होने वाला है. वैसे तो डूसू का चुनाव हमेशा दिलचस्प वाला होता है और देश भर की नजर उसके नतीजों पर रहती है. लेकिन इस बार का चुनाव खास दिलचस्पी वाला होगा. इसके दो कारण हैं.

पहला तो यह कि पेपर लीक और परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्रों व युवाओं के प्रदर्शन के बाद यह पहला चुनाव है. चुनाव से ठीक पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैम्पस के पास सत्य निकेतन में एक पीजी हॉस्टल की इमारत गिरने की घटना भी हुई है, जिसमें पांच छात्रों सहित

सात लोगों की मौत हुई है. इसके बाद से दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए हॉस्टल की कमी एक बड़ा मुद्दा बनी है.

डूसू चुनाव में दिलचस्पी का दूसरा कारण यह है कि जंतर मंतर पर धरने का साझा तौर पर नेतृत्व करने वाली आईसा ने इस बार दूसरे कम्युनिस्ट छात्र संगठन एसएफआई से हाथ मिलाया है. ध्यान रहे एसएफआई सीपीएम का छात्र संगठन है, जबकि आईसा सीपीआई माले का संगठन है. आईसा की नेहा बोरा भी जंतर मंतर पर 20 दिन तक भूख हड़ताल पर रही थीं. उसके बाद वे देश भर के दौरे कर रही हैं. वे डूसू का चुनाव लड़ाएंगी. दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ आने का बड़ा असर चुनाव नतीजों पर होगा. अगर 'जेन जी' को अपनी नाराजगी जतानी है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों की बजाय वे उस संगठन को चुन सकते हैं, जिसने छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व किया था. भाजपा को इसका अंदाजा है. तभी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 'जेन जी' को संबोधित किया था.